अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–12 अंक–232 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ गुरुवार 21 दिसम्बर 2023 पृष्ठ – 4 मूल्य–3 रूपया

संक्षिप्त समाचार

वन मंत्री अचानक पहुँचे लखनऊ जू ,देखी वन्यजीवों के बाड़ों की व्यवस्था

सुरक्षा व्यवस्था और अधिक चाक–चौबंद करने का सुनाया फरमान

दरियाई घोड़े के हमले में मृतक सूरज की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने का निदेशक को दिया निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ.अरूण कुमार सक्सेना ने आज प्रातः नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ जू का औचक निरीक्षण किया। वन्यजीवों के बाड़ों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक चाक–चौबंद करने के निर्देश दिये। यह भी कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ कर्मचारियों की भी सुरक्षा के बेहतर प्रबंध किया जाय। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना भविष्य में घटित न होने पाये अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।डॉ. सक्सेना ने विगत दिनो चिड़ियाघर में दरियाई घोड़े के हमले में मृतक सूरज की पत्नि को संविदा पद नौकरी देने के लिए निदेशक जू को निर्देश दिये। डब्ल्यूटीआई एवं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ एजेन्सियों एवं लेबर डिपार्टमेंट से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। चिड़ियाघर में साफ–सफाई के बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने जू में स्थित बाड़ों का निरीक्षण करते हुए कहा कि वन्यजीव सुरक्षा के लिए बनी बैरीकेटिंग को चुस्त–दुरूस्त कराया जाये। कोई बैरीकेटिंग क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ इनकी देखभाल में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। विशेषज्ञों की देखरेख में ही कर्मचारियों को बाड़े में जाने की अनुमति दी जाये और दरियाई घोड़े के उग्र होने की जांच चिकित्सक से कराई जाय। साथ ही समय–समय पर सभी वन्यजीवों का चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता रहे।

डिप्टी सीएम पहुंचे पीजीआई, दुर्घटना की ली जानकारी

लखनऊ। एसजी पीजीआई में हुए अग्निकांड के बाद बुधवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल पहुंच कर मरीजों का हाल–चाल जाना। दुर्घटनास्थल पर चिकित्साधिकारियों के साथ पहुंच कर प्रकरण की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस हादसे की उच्चस्तरीय जांच कराई जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी स्थित पीजीआई पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीधे घटनास्थल का रुख किया और अस्पताल प्रबंधन से घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल दुर्घटनास्थल को सील कर दिया गया है। साफ–सफाई कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों का पता चलेगा। उन्होंने बताया कि पीजीआई सहित प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों एवं ऑपरेशन थियेटरों का फायर ऑडिट कराया जा रहा है।

सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ,कार्यक्रम में जेपी नड्डा और सीएम योगी रहे मौजदू

सीएम ने कहा, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएंगे, हर गांव में होगा स्टेडियम

बस्ती। जिले में सांसद खेल महाकुंभ का आज से आगाज हो रहा है। 20 दिसंबर से शुरू होने वाले यह कार्यक्रम 29 दिसंबर तक चलेगा, कार्यक्रम का शुभारंभ करने सीएम योगी आदित्यनाथ व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती पहुंचे। मंच पर सांसद हरीश द्विवेदी सहित बीजेपी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से इंसेफेलाइटिस समाप्त हो रहा है। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50 हजार बच्चों को निगल लिया था। उसे प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों के अनुरूप समाप्त कर दिया गया है। पीएम के साथ खेल कूद महाकुंभ प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं। पीएम मोदी खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को प्रोत्साहित किया है। प्रदेश ने संकल्प लिया है कि खेल व खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएंगे। हर गांव में होगा स्टेडियम। हम जानते हैं कि पिछले साढ़े नौ वर्ष के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, ये नया भारत जिसमें 142 करोड़ लोगों को गौरव के साथ आगे बढ़ने, और बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। चेहरा देखकर नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, वंचित पिछड़ा, महिलाएं, युवा, इस सभी को शासन की योजनाओं में भागीदार बना करके, उनके जीवन में परिवर्तन करने का जो कार्य पिछले साढ़े नौ वर्ष के अंदर जो कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम हम सबको देखने को मिला है, और

यह हम सब जान रहे हैं कि जब मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता आई थी, तब यह देश दुनिया की 11 वीं 12 वीं अर्थ व्यवस्था के रूप में जाना जाता था और हमारा यह सौभाग्य है। एक यशस्वी नेतृत्व में आज भारत की अर्थ व्यवस्था देश, दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थ व्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। कहा कि जिस गति से भारत बढ़ रहा है, आने वाले तीन चार वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। इसमें भारत की अर्थ व्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ हर भारत वासी को जुड़ना है। हर भारत वासी जुड़ेगा, तो ये अर्थ व्यवस्था की मजबूती होने का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली आना, हर एक के जीवन में परिवर्तन आना और इसी का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। जहां चेहरा देखकर नहीं बल्कि सभी वर्ग को शासन की योजनाओं का भागीदार बनाया जा रहा है। देश के अंदर सामर्थ्य प्रदान किया जा रहा है। पांच सौ खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार जैसे पदों पर नौकरी दी गई है। खेल कोटे से पांच सौ पद के लिए जल्द आवेदन मांगे जाएंगे। जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करेगा उसे सरकारी नौकरी और आजीवन भरण पोषण की व्यवस्था की जाएगी।कहा कि प्रत्येक जिले में एक खेल सेंटर बनाने का काम चल रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जुबान फिसल गई, उन्होंने शुभारंभ की जगह समापन बोल दिया। उन्होंने कहा कि मेरा यह सौभाग्य है कि इस खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में योगी आदित्य नाथ के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहा कि अभी–अभी योगी जी कह रहे थे कि साढ़े नौ साल में नाए भारत का दर्शन हो रहा है और उस नए भारत का प्रतिबिंब मुझे यहां नौजवानों में दिख रहा है। वह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुझे जानकर खुशी है कि एक लाख विद्यार्थियों के व 50 हजार खिलाड़ियों के क्रम से प्रारंभ करते हुए आज साढेध् तीन लाख खिलाड़ी व साढ़े चार लाख विद्यार्थी इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं, उनका बहुत–बहुत अभिनंदन। देश को चलाने के लिए नेतृत्व और नीति और नियम और कार्यक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आज हम खेल की बात कर रहे हैं। नौजवनों से पूछा क्या कारण था कि 70 सालों में एशियन गेम्स में कभी भी पहले इतने मेडल नहीं आए, जो मेडल पिछले एशिनय गेम्स में सौ से ज्यादा आए। इस बात को हमको समझना चाहिए। कहा कि क्या कारण था कि टोक्यो के ओलंपिक के पहले भारत कभी भी ओलंपिक में इतनी बड़ी संख्या में मेडल नहीं ले सका। वह लेने का सौभाग्य आज भारत को मिला तो वो टोक्यो ओलंपिक में मिला और मोदी जी के नेतृत्व में मिला। मोदी ने भारत को इंडिया के दायरे से निकालकर भारत के दायरे में पहुंचा दिया है, इस बात को समझना चाहिए। कहा कि 2014 में खेल में सिर्फ एक हजार दो सौ 19 करोड़ का बजट था, लेकिन आज खेल में तीन हजार तीन सौ 97 करोड़ का बजट है, 2014 से पहले कोई ओलंपिक पोडियम टीम नहीं थी। अब टारेगेट पोडियम ओलंपिक टीम बनी है।

सांसद खेल महाकुंभ शुभारंभ अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रभारी मंत्री राकेश सचान, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, युवा कल्याण विभाग मंत्री गिरीश चंद्र यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, क्षेत्रीय प्रभारी गोविंद नाराण शुक्ल, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी, जिला प्रभारी समीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, हरैया विधायक अजय सिंह, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, रवि सोनकर आदि मौजूद रहे।

चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न प्रदान किया जाये : रालोद

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग की पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने जीवन पर्यंत शोषितों और और वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ी है। चौधरी साहब को जब भी अवसर मिला उन्होंने किसानों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अपनी पूरी क्षमता से कार्य से किया।रोहित अग्रवाल ने पत्र में कहा कि चौधरी सहाब कहते थे कि देश कि ष्समृद्धि और खुशहाली का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है और इसलिए उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ग्रामीण भारत के विकास हेतु समर्पित कर दिया। चौधरी चरण सिंह ने कई संवैधानिक पदों को सुशोभित किया,वे उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री रहे, इसके अलावा वे केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री, उप–प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री रहे।वे भारत के इकलौते राजनेता हैं, जिन्हें किसान मसीहा कहलाने का गौरव प्राप्त है, यह गौरव उन्हें प्रेम करने वाली सम्मानित जनता ने प्रदान किया है। राजनीतिक कारणों के चलते सरकार लगातार

इस बात को नजरअंदाज कर रही है, यह प्रश्न बार–बार खड़ा होता है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अब तक क्यों नहीं दिया गया, क्या वे वंचित और किसानों के नेता थे इसलिए उन्हें अब तक भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया, चौधरी चरण सिंह पूरे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने जीवन में हर वर्ग के लिए संघर्ष किया, हर वर्ग के उत्थान का प्रयास किया। सरकार द्वारा चौधरी साहब के बलिदान को नजरअंदाज करना इस देश की जनता का अपमान हैं। रोहित अग्रवाल ने कहा कि 23 दिसंबर को जब पूरा देश चौधरी साहब की जयंती किसान दिवस के रूप मना रहा होगा,ऐसे खास दिन पर सरकार जनता की भावनाओं की कदर करते हुए चौधरी साहब के लिए भारतरत्न की घोषणा कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करे।

उन्होंने आशा कि पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानो के मसीहा चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की घोषणा करने हेतु हर सम्भव प्रयास करेंगे।

ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस की छूट का लाभ लेकर बकाया विद्युत बिल जमा करने की अपील

घरेलू उपभोक्ताओं एवं किसानों को मिल रही 80 प्रतिशत की छूट

ओटीएस में 35 लाख उपभोक्ताओं ने लिया लाभ : शर्मा

लखनऊ। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत मंगलवार तक पूरे प्रदेश में 35 लाख उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया और इससे 3500 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई। उपभोक्ताओं को 1200 करोड़ रूपये का फायदा हुआ। विद्युत चोरी के मामलों में 72 हजार लोगों के कानूनी और आपराधिक मामलों को भी हल किया गया।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश में चल रही ओटीएस उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही प्रभावी और लाभकारी योजना रही। अब यह योजना अपने अन्तिम दौर में चल रही है। इस योजना का तीसरा चरण 31 दिसम्बर तक है। 31 दिसम्बर को योजना समाप्त हो रही है। इसके पश्चात योजना की अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। अभी भी जिन लोगों के विद्युत बिलों के बकाये या विद्युत चोरी के मामले लम्बित हैं, वे जल्द से जल्द ओटीएस का लाभ लेकर अपनी विद्युत सम्बंधी समस्याओं का समाधान करा लें। प्रदेश में ओटीएस को "जल्दी आएं, ज्यादा लाभ पाएं" की कसौटी पर चलायी गयी थी। किश्तों में भी भुगतान करने की व्यवस्था दी गयी थी। 31 दिसम्बर के पश्चात जिस किसी के भी विद्युत बिलों के बकाये और विद्युत चोरी सम्बंधी प्रकरण लम्बित रह जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ओटीएस के तीसरे चरण में भी 01 किलोवॉट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है। इसी प्रकार विद्युत चोरी के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है। योजनान्तर्गत इस अवधि में 01 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, 03 किलोवॉट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओ को 40 प्रतिशत के साथ निजी संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है। ओटीएस के तहत मंगलवार तक पूर्वांचल डिस्काम में 9.84 लाख, मध्यांचल में 9.85 लाख, दक्षिणांचल में 7.42 लाख, पश्चिमांचल में 7.67 लाख, केस्को में 18 हजार उपभोक्ताओ ने ओटीएस में पंजीकरण करा कर सरचार्ज में छूट का लाभ लिया। विद्युत चोरी के मामलों में पूर्वांचल डिस्काम ने 19,080, मध्यांचल ने 11,165, दक्षिणांचल ने 18,676, पश्चिमांचल ने 21,686 तथा केस्कों ने 1,385 लोगों के प्रकरणों को समाप्त किया। ऊर्जा मंत्री ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि ओटीएस में दी गयी छूट का लाभ लेकर अपना बकाया जमा कर दें। अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि बकाये के भुगतान के लिए बकायेदारों को प्रेरित किया जाय।

डीएम ने की विकास के कामों की समीक्षा

डीआईओएस और ईओ नानपारा की सैलरी रोकने के निर्देश, मीटिंग से एबसेंट होने पर कार्रवाई

बहराइच, (यूएनएस)। जिले में डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बैठक के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नानपारा की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होनें विभिन्न विभागों की मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर रैंकिंग की समीक्षा के दौरान "बी,सी,डी,ई" श्रेणी के रैकिंग वाले विभागों पर कड़ी अप्रसन्न्ता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि सम्बन्धित विभाग विशेष प्रयास कर महीने के अन्त तक रैंकिंग में अपेक्षित सुधार लाए, अन्यथा सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए वेतन बाधित करने की कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने यह निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर विभागीय प्रगति की फीडिंग जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं अपनी देख–रेख में कराए। बैठक के दौरान पंचायती राज, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, समाज कल्याण, लोक निर्माण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, पशु पालन इत्यादि विभागों के प्रगति की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। 50 लाख से अधिक एवं 50 लाख से कम लागत की निर्माण परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश की जिन परियोजनाओं की भूमि उपलब्ध हो गयी है। वे निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। यदि कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू नहीं कराती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस सम्बंध में प्रशासकीय विभागों को भी निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से समन्वय कर परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराएं, ताकि परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हो सके। प्रशासकीय विभाग अपनी विभाग की निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित कराए जाने के लिए समय–समय पर निर्माण परियोजनाओं का स्वयं निरीक्षण करते रहे। जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, उसे अविलम्ब सम्बन्धित विभाग को हैंडओवर करा दिया जाए, ताकि परियोजनाओं को जन उपयोग में लाया जा सके। इस अवसर पर सीडीओ रम्या आर और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।

रोडवेज कर्मियों की जायज मांगो के समाधान का एमडी ने दिया आश्वासन

कर्मचारियों का आज नही होगा धरना

लखनऊ, (यूएनएस)। रोडवेज कर्मियों की समस्याओं को लेकर आज राज्य परिवहन निगम के एमडी ने कर्मचारी संगठन के साथ बैठक की। एमडी ने आश्वस्त किया कि जायज और आवश्यक मांगों का समाधान किया जायेगा। प्रबंध निदेशक के साथ यूनियन द्वारा प्रेषित18 सूत्रीय मांग पत्र पर सोहार्द पूर्ण वार्ता हुई जिसमें यूनियन की तरफ से बी डी मिश्रा प्रांतीय अध्यक्ष तेज बहादुर शर्मा प्रांतीय महामंत्री राजकुमार तोमर प्रांतीय संगठन मंत्री टी एन सिंह प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र पांडे प्रांतीय संयुक्त मंत्री स्वदेश मिश्रा कोषाध्यक्ष के एस बाजपेई विशेष आमंत्रित सदस्य दिनेश मणि मिश्रा प्रांतीय संयुक्त मंत्री उपस्थित रहे। वार्ता में कहा गया कि 10 फीसदी डीए अंतिम चरण में है प्रयास कर शीघ्र लागू कराया जाएगा। संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का 8 प्रतिशत अभी बढ़ाया गया है तथा इसी क्रम में आउटसोर्सिंग का भी बढ़ाया गया है। निगम में नॉन आईटीआई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की क्षेत्र स्तर पर कमेटी बनाकर सीधे निगम से आबद्ध किया जाएगा। निगम में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 6000 कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव बन रहा है। परिवहन निगम के 301 मार्गो का राष्ट्रीयकरण प्रस्ताव गया है। इसमें से 132 मार्ग शीघ्र ही राष्ट्रीयकृत कर दिए जाएंगे तथा 1526 मार्ग राष्ट्रीयकरण हेतु शासन को प्रेषित किये जाएगे निगम एवं प्राइवेट बसों में अधिभार अंतर को समान करने हेतु कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। 2001 तक के संविदा चालको परिचालकों को नियमित करने हेतु कार्रवाई चल रही है । 890 मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियमितनियुक्ति हेतु पत्रावली शासन स्तर पर गतिशील है। प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने कहा कि शासन स्तर की मांगो के निस्तारण हेतु संगठन से शीघ्र वार्ता कराई जाएगी जिसमें निगम प्रबंधन एवं संगठन दोनों मिलकर संयुक्त प्रयास से समस्याओं का समाधान करा लेंगे। प्रबंध निदेशक के अनुरोध पर प्रस्तावित 21 दिसम्बर का धरना एक माह के लिए स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया। यदि एक माह के अंदर सहमति बने बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन पुनः प्रारंभ किया जाएगा।

अपर खंड पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर के 11 निरीक्षण भवनों की चहारदीवारी हेतु 50 लाख स्वीकृत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहारनपुर में अपर खंड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित 11 निरीक्षण भवनों की चारदीवारों के निर्माण कार्य हेतु 50 लाख रुपए की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर कर दिया गया हैं।जारी शासनादेश में यह निर्देश दिए गए हैं। कि मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था,विभाग का होगा। परियोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा। विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां, पर्यावरण क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया संविदा कर्मियों को आउटसोर्स के माध्यम से लिए जाने का विरोध

मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव को भेजा ज्ञापन

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि उनके संज्ञान में लाया गया है कि 7 दिसंबर एवं 11 दिसम्बर को निदेशक महिला कल्याण ने विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए बैठक किया था। बैठक के दो कार्यवृत्त जारी किए गए हैं। पहला कार्यवृत्त 7 दिसंबर को जारी किया गया है, जिसमें संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों को सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से रखे जाने का निर्णय लिया गया है। दूसरा कार्यवृत्त 19 दिसंबर को जारी किया गया है जिसमें विभागीय योजनाओं की समीक्षा के साथ संविदा कर्मियों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लिए जाने के निर्णय को पुनरू दोहराया गया है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिख कर यह अवगत कराया है कि वित्तीय नियमों के अंतर्गत पद की प्रकृति में बदलाव नहीं किया जा सकता है। संविदा कर्मियों की नियुक्ति नियमानुसार विज्ञापन निकालकर चयन समिति गठित करके किया गया है। कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है। महिला कल्याण विभाग द्वारा केंद्रीय सहायतित समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है। नियुक्त कर्मी 2012 से निरंतर संविदा पर कार्य कर रहे हैं ।11 साल बाद अचानक ही संविदा के पदों पर कार्यरत कर्मियों को आउटसोर्स में परिवर्तित करने का निर्णय लिए जाने से पूरे प्रदेश के हर विभाग में विसंगति उत्पन्न हो जाएगी। जहां एक तरफ सरकार आउटसोर्स पर रखे गए व्यक्तियों को कर्मचारी नहीं मानती है, वहीं दूसरी तरफ निदेशक महिला कल्याण की कार्यवृत्त के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी संविदा के पदों पर काबिज हो जाएंगे। यदि यह योजना महिला कल्याण विभाग में लागू हो जाती है तो इसका असर प्रदेश के समस्त विभागों में पड़ेगा। विशेष कर इस निर्णय से स्वास्थ्य विभाग प्रभावित होगा ।जहां पर लगभग 100000 संविदा कर्मचारी केंद्रीय सहायतित योजना एनआरएचएम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों को आउटसोर्स में बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी और प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारी संविदा कर्मी के लिए विज्ञापित पदों पर आ जाएंगे।सरकार संविदा कर्मियों को समय–समय पर नियमित करती रही है ,परंतु आउटसोर्स कर्मचारी के लिए नियमितीकरण की कोई नियमावली अभी तक नहीं है। महिला कल्याण विभाग के इस निर्णय से सभी आउटसोर्स कर्मचारी जिनकी संख्या लाखों में है, संविदा के पदों पर काबिज हो जाएंगे और उनको नियमित किए जाने का आधार बन जाएगा। परिषद ने अपने पत्र में मुख्य सचिव से इस तरह की अनियमित पद प्रतिस्थापना रोके जाने का अनुरोध किया है। यदि शीघ्र ही इस पर निर्णय नहीं होता है ,तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा के पदों पर रखने की मांग करेगी। जिसको मानने के लिए महिला कल्याण का उदाहरण देकर सरकार को बाध्य किया जा सकता है। यह व्यवस्था लागू हो जाने से लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करने का रास्ता खुल जाएगा एवं सरकार को खजाने से हजारों करोड़ों रुपए व्यय करने पड़ेंगे।

सम्पादकीय

लोकतंत्र के लिए खतरनाक है थोक में सांसदों का निलम्बन

सोमवार का दिन भारत के संसदीय इतिहास के सर्वाधिक काले दिनों में से एक कहा जायेगा जब लोकसभा के 78 सदस्यों को निलम्बित कर दिया गया। ये सांसद पिछले बुधवार (13 दिसम्बर) को संसद में कुछ युवकों द्वारा किये गये प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़े थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे सदन के कामकाज में व्यवधान मानते हुए इन्हें सत्र के लिए निलम्बित कर दिया। इसी विषय पर 14 तारीख को लोकसभा के एक तथा राज्यसभा के 13 सदस्यों को भी निलम्बित किया गया था। इस प्रकरण में अलग–अलग तरीकों से व विभिन्न नियमों का हवाला देकर कुल 151 सदस्यों को अब तक निलम्बित कर दिया गया है। थोक के भाव में सांसदों को बाहर का रास्ता दिखलाना यह दर्शाता है कि संसद को पूरी तरह से विपक्ष मुक्त बनाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो चलाया जा रहा है वह अपने चरम पर पहुंच गया है। लोकतंत्र के लिए यह बेहद खतरनाक है। किसी भी जनतांत्रिक प्रक्रिया में इसे अनुचित ही माना जायेगा क्योंकि सदन आखिर बना ही चर्चा के लिए है और विपक्ष का काम सरकार से प्रश्न पूछना ही है। सरकार का दायित्व है कि वह जवाब दे। हंगामे का जो कारण था, वह इस बात के लिए पर्याप्त आधार है कि सांसद उद्वेलित हों। जिस प्रकार से दो लोग लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में कूद पड़े थे और उनमें से एक व्यक्ति एक से दूसरी बेंच पर छलांगें लगाकर भागता रहा, उससे संसद की सुरक्षा व्यवस्था में गम्भीर खामी सामने आई थी। यह मामला सांसदों की सुरक्षा से तो जुड़ा ही है, इसकी गम्भीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह कृत्य संसद पर 22 वर्ष पहले हुए आतंकी हमले के ही दिन हुआ। विदेश में बैठे एक अलगाववादी नेता ने इसी दिन पर हमले की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद जिस तरीके से ये साधारण से दिखने वाले व्यक्ति आये, एक ने पीला धुआं फैलाया और शेष ने सदन के बाहर नारेबाजी की, सारा कुछ अपने आप में मसले की नजाकत व उसे देश की सर्वोच्च पंचायत के भीतर बहस योग्य तो बनाता ही है। फिर, इस पर अगर विपक्ष गृह मंत्री से जवाब नहीं चाहेगा तो और किससे मांग की जायेगी? जिस दिन से यह घटना हुई है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं सदन से गायब हैं। यह मामला तो ऐसा है कि उन्हें खुद ही उपस्थित होकर सदस्यों को संतुष्ट करना था। मजेदार बात तो यह है कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने का आश्वासन मोदी सदन के बाहर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कमियों को दूर किया जा रहा है। यह बात उन्हें सदन के भीतर कहने से आखिर क्या गुरेज है, यह समझ से परे है। मोदी व उनकी सरकार का इतिहास ऐसा ही रहा है। 2014 और 2019 में भी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों को निलम्बित करने के उदाहरण देश देख रहा है। एक तो वे या उनके जिम्मेदार मंत्री सदन में जवाब नहीं देते और सदन में जब सदस्य इसकी मांग करते हैं तो उन्हें निलम्बित कर दिया जाता है। हाल ही में मणिपुर और गौतम अदाणी के मामलों में भी यही देखा गया। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी व टीएमसी की महुआ मोइत्रा की सदस्यता छीनी गई। तरीका चाहे जो भी रहा। इस मामले में मोदी की कथनी व करनी में बड़ा अंतर नजर आता है। अभी इसी सत्र के शुरुआती अवसर पर मोदी का आग्रह था कि विपक्ष सकारात्मक रवैया अपनाये। उन्होंने कहा भी था कि प्रतिपक्ष हाल के विधानसभा चुनावों में पराजय का गुस्सा छोड़कर सदन में आये। इससे देश का उनकी ओर देखने का नजरिया भी बदलेगा। यह तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा था लेकिन मोदी ने यह भी कहा था कि विरोधी नेता सरकार की गल्तियां बताए। उन्होंने विपक्षी दलों को सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। उसके पहले नये संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर भी प्रधानमंत्री इसी तरह की बातें करते नजर आये थे। अब विपक्ष जब सरकार की खामियां सामने ला रहा है, तो मोदी व शाह सदन में जवाब देने से बचते फिर रहे हैं। यूं तो मोदी परस्पर संवाद के लिए हमेशा अपनी व सरकार की तैयारी बतलाते हैं परन्तु सच्चाई तो यह है कि वे जरूरी मुद्दों पर न तो सदन के भीतर चर्चा कराना चाहते हैं और न ही बाहर। सदन के अंदर जब भी उन्हें कहते सुना गया है तो वह है विपक्ष पर हमला और इतिहास में जाकर पिछले 75 वर्षों की बातें करना। किसी भी विषय पर तार्किक, तथ्यात्मक, आंकड़ों के साथ और बिन्दुवार जवाब देने की बजाये वे संवाद को अनर्गल और कटु मोड़ देते हुए ही दिखाई दिये हैं। सदन के भीतर उनकी कही बातों पर मेजें थपथपाने वाले लोगों का बहुमत है तो बाहर आयोजित होने वाली उनकी सभाओं में पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो उनकी तथ्यहीन बातों पर श्मोदी मोदीश का शोर मचाने में माहिर हैं। सदन के भीतर की ही तरह बाहर भी वे किसी के सवालों का जवाब नहीं देते। प्रेस कांफ्रेंस वे करते नहीं और कभी–कभार वे मीडिया से कोई बात करते भी हैं तो वह एकतरफा। सवाल वे लेते नहीं। तुर्रा यह कि इसके बाद भी वे भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। कांग्रेस मुक्त व विपक्ष मुक्त भारत का नारा देने वाले मोदी अपने विरोधियों को जिस योजनाबद्ध तरीके से खत्म कर रहे हैं, उसी के एक विस्तार कार्यक्रम की तरह संसद के दोनों सदनों से थोक के भाव में सदस्यों को निलम्बित किया जा रहा है। कहने को तो यह निलम्बन लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति का निर्णय लग सकता है परन्तु इन दोनों का जो व्यवहार देखा गया है उसके मुताबिक दोनों ने सरकार व भाजपा के अंग की तरह यह काम किया है। ये निलम्बन ऐसे वक्त पर हुए हैं जब इस सरकार का यह लगभग अंतिम सत्र है। समझा जाता है कि अगले सत्र में केवल अनुपूरक बजट ही पेश किया जायेगा क्योंकि अप्रैल में आचार संहिता लागू हो सकती है ताकि मई में लोकसभा चुनाव कराये जा सकें। ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार का इरादा साफ है कि वह कई महत्वपूर्ण बिल संसद में बिना चर्चा के पारित कराना चाहती है। अभी ही अनेक विधेयक बगैर चर्चा के पास होकर कानून का रूप ले चुके हैं। सरकार का उद्देश्य विरोधी सदस्यों को दोनों सदनों के बाहर ही रखना है। फिर, जैसे कि कयास लगाये जा रहे हैं, कि 22 जनवरी, 2024 को मोदी के हाथों तय किये गये राममंदिर के उद्घाटन के तुरन्त बाद लोकसभा के मध्यावधि चुनावों की घोषणा हो सकती है– इन चुनावों की तैयारी के लिए भाजपा अपने लिए विरोध–मुक्त वातावरण बनाने में जुटी है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए एकदम स्पष्ट है कि दोनों सदनों के संचालक (क्रमशरू अध्यक्ष व सभापति) सरकार के मददगार बनकर काम कर रहे हैं। वे भी नहीं चाहते कि सरकार के सामने कोई भी विपक्ष खड़ा हो जो मोदी, उनकी सरकार व पार्टी को असहज स्थिति में डाल सके। इन तरीकों से हो सकता है कि मोदी अगला चुनाव फिर से जीत जायें परन्तु ऐसे फैसले लोकतंत्र के लिये घातक हैं।

भारतीय शेयर बाजार में तेजी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित

भारतीय शेयर बाजार फिलहाल अजेय नजर आ रहा है। शेयर बाजार नयी ऊंचाइयों को छू रहा है और इसके साथ ही निवेशक मालामाल हो रहे हैं। शुक्रवार को इंट्रा–डे ट्रेडिंग में बीएसई सेंसेक्स करीब 1000 अंक बढ़ गया और एनएसई इंडेक्स करीब 300 अंक चढ़ गया है। इस तरह के उत्साहपूर्ण उछाल के बाद अनिवार्य रूप से सवाल उठता है कि क्या ऊपर की ओर रुझान कायम रहेगा या कोई प्रतिक्रिया होगी और कुछ सुधार या गिरावट होंगे? हो सकता है, नवीनतम एआई मॉडल से एक प्रकार का उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि एआई के जादूगर भी ऐसे सवालों से घबरा जायेंगे। वृद्धि पर समग्र प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, कुछ बाजार विशेषज्ञों को कम से कम इतना तो लगता ही है कि महीने के अंत में सुधार हो सकता है। लेकिन यह अभी भी किसी का अनुमान नहीं है। अधिक प्रासंगिक प्रश्न यह हो सकता है कि वित्तीय बाजारों में ऐसी आशावाद को कौन से कारक प्रेरित कर रहे हैं। इस बार जवाब ढूंढने के लिए दूर–दूर तक नजर नहीं दौड़ानी पड़ेगी। इस बार अनुकूल संयोग है और तेजी कुछ देर तक चल सकती है। लंबे समय के बाद कम मुद्रास्फीति हाल का प्रमुख सकारात्मक विकास हो सकता है। कम मुद्रास्फीति एक आसान धन नीति और इसकी दरों में नीचे की ओर संशोधन की उम्मीदों को बढ़ावा देती है। इधर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने रेट कट का चक्र शुरू करने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा है। बल्कि सावधानी बरतने की बात की है और चेतावनी दी है कि आरबीआई मुद्रास्फीति प्रिंटों की बारीकी से निगरानी कर रहा है। लेकिन फिर, केंद्रीय बैंकों के बड़े भाई, यूएस फेड के अध्यक्ष, जेरोम पॉवेल ने बाजार की अपेक्षा से अधिक तेजी से दर संशोधन चक्र की संभावना का संकेत दिया है। इसने बाजार के लिए एक मादक कॉकटेल के रूप में काम किया था। लेकिन यहां और अभी के लिए इस तरह के बेतहाशा उतार–चढ़ाव बहुत अच्छी बातें हैं। ये फीडबैक चौनलों की नकल करते हैं जो एक प्रकार के उत्साह को बढ़ावा देते हैं, भले ही ऐसी चीजें अल्पकालिक होती हैं। हालांकि शेयर बाजार में निवेशक बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन बाजार में इस तरह के व्यापक उतार–चढ़ाव एक प्रकार का श्फील–गुज्ज्य कारक पैदा करते हैं जो उपभोक्ता भावनाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करता है। इससे कम से कम निवेशकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उपभोग मांग में बढ़ोतरी हो सकती है। जब बीएसई सेंसेक्स 70,000 को छू गया था, तो यह ऊंचा दिख रहा था। अब, यह 71,000 से आगे बढ़ रहा है। देखिए किस गति से ये चीजें हो रही हैं। जहां सेंसेक्स को 1,000 अंक चढ़ने में 93 सत्र लगे, वहीं 70,000 से 71,000 तक पहुंचने में इसे केवल एक दिन लगा। तर्कसंगत रूप से कहें तो यह अनिश्चितता का संकेतक है। जब मूड में इतना तीव्र बदलाव होता है तो प्रतिक्रियाएं भी उतनी ही तीव्र हो सकती हैं। लेकिन, इसे एक पल के लिए छोड़ दें, और आइए हम उन कारकों की जांच करें जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं और ये कितने स्थिर हो सकते हैं। मुख्य रूप से, यह कुछ वैश्विक रुझानों का प्रतिबिंब है जो सीमाओं के पार धन के प्रवाह को प्रभावित कर रहे हैं। जैसा कि हमने उल्लेख किया था, अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व ने इस सप्ताह की शुरुआत में संकेत दिया था कि अमेरिकी मुद्रास्फीति दरों में नरमी को देखते हुए, प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति को समाप्त किया जा सकता है और ब्याज दरों में संभावित कटौती की जा सकती है। अमेरिकी मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 7.5 फीसदी से घटकर अब लगभग 3.5 फीसदी हो गई है। यह एक मजबूत विकास है। इसे कहां तक बनाये रखने की उम्मीद है? क्या मजबूत मूल्य रुझान की वापसी हो सकती है? इसकी संभावना नहीं है क्योंकि अमेरिकी वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति की तुलना में तेज चल रही है और अब इसमें कमी आने की उम्मीद है। दूसरे, तेल की कीमतें भी गंभीर निशान छोड़ रही हैं। फेड अध्यक्ष के बयान पर उत्साहजनक प्रतिक्रियाओं की लहर दौड़ गई और अमेरिकी वित्तीय बाजार उत्साहित हो गये। अमेरिकी शेयर बाजार में निवेशकों द्वारा शेयरों की भारी खरीदारी देखी गई और परिणामस्वरूप अमेरिकी बाजार चढ़ गया। दूसरी ओर, अमेरिकी दर में कटौती की प्रत्याशा में, निवेशकों ने अपने विकल्पों की समीक्षा की और अन्य वित्तीय बाजारों में अवसरों की तलाश कर रहे हैं। बॉन्ड बाजार के निवेशकों को भविष्य में कमाई की संभावनाएं क्षीण लग रही हैं और इसलिए वे अन्य बाजारों और अन्य उत्पादों की ओर देखने के लिए बाध्य हैं। धन भारतीय बाजारों में क्यों आना चाहिए? ऐसा इसलिए कि वैकल्पिक बाजार अनाकर्षक दिख रहे हैं। चीन, हाल तक संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा सबसे बड़ा बाजार था, जो धन आकर्षित करता था। हालांकि, चीनी बाजार स्वयं कमजोर हो रहा है और वहां राजनीतिक मालिक चीनी अर्थव्यवस्था के हर विकास को नियंत्रित करना चाह रहे हैं।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक कदमों से चीन में बाजार की धारणा बुरी तरह प्रभावित हुई है और बड़ी संख्या में कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। चीन की कंपनियों ने चीनी शेयर बाजार अधिकारियों को लापता मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बारे में सूचित किया है। इस खबर के परिणामस्वरूप चीनी शेयर बाजारों में गिरावट आई है।

बदले में, भारतीय बाजारों में बढ़त जारी है। सबसे पहले, भारत में व्यापक आर्थिक स्थिति अनुकूल है। हाल तक, कीमतें बढ़ रही थीं और सकारात्मक भावनाओं को खतरे में डाल रही थीं। ऊंची ब्याज दरों को लेकर रिजर्व बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि, हाल ही में कीमतों में नरमी आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने कम प्रिंट दिया है, हालांकि कुछ उछाल देखा गया है। भारत में ब्याज दरें बढ़ने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। इसलिए, निवेश की संभावनाएं उज्ज्वल हैं। विशेषज्ञ विदेशों से अत्यधिक धन प्रवाह की उम्मीद कर रहे हैं और इससे शेयर बाजार में तेजी आ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक दिसंबर के पहले दस दिनों में प्रतिदिन औसतन 4000 करोड़ रुपये निवेश कर रहे हैं। पिछले महीने विदेशी निवेशकों ने 9000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ये सभी बातें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दरों में कटौती की घोषणा से पहले की हैं।

ये भारत में निवेश को लेकर सकारात्मक भावनाओं के संकेत हैं और यह जारी रहने की संभावना है। निवेशक निवेश में बने रहने का लाभ उठा रहे हैं। अगला वर्ष उन लोगों के लिए निवेशकों का वर्ष होने की संभावना है जो भारतीय इक्विटी में निवेश करने के लिए संसाधन और साहस जुटा सकते हैं।

लोकतंत्र का तमाशा और इंडिया की राह

हमें पहले जीतकर आना होगा, उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से हमारे चुने हुए सांसद तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री पद पर कौन बैठेगा। ये महत्वपूर्ण बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को दिया है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक मंगलवार 19 दिसम्बर को दिल्ली में हुई, जिसमें गठबंधन के सभी 28 दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भाजपा के खिलाफ बने इस विपक्षी गठबंधन की इस बार की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। मुंबई में हुई तीसरी बैठक के बाद अब जाकर हुई इस चौथी बैठक में काफी लंबा अंतराल रहा, और इस दरम्यान इंडिया गठबंधन को लेकर जितने किस्म की अफवाहें मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा सकती थीं, वो सब फैलाई गईं। इन अफवाहों में दस बार इंडिया गठबंधन में टूट पड़ी, उसके नेताओं की राहें अलग हो गईं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नामों को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते हुए यह भी कहा गया कि ये सब कांग्रेस के खिलाफ एक हो सकते हैं। इस बीच हुए विधानसभा चुनावों में मध्यप्रदेश में सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच हुए मतभेद को सीधे अखिलेश यादव की कांग्रेस को चुनौती के तौर पर पेश किया जाने लगा। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार को सीधे इंडिया की हार से जोड़ा गया और लगे हाथ ये तर्क भी दिया गया कि अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका कमतर हो जाएगी। अब तक कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन अब बाकी दल उसकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन ये तमाम दावे मंगलवार को तब खोखले साबित हो गए, जब बैठक के बाद सभी दलों ने श्री खड़गे को ही प्रेस को संबोधित करने के लिए कहा। इससे पहले खबर ये भी आई कि बैठक में ममता बनर्जी ने गठबंधन के संयोजक पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रस्तावित किया और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया। हालांकि अभी संयोजक पद के लिए किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जिन ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा था कि वे कांग्रेस को अग्रणी भूमिका में नहीं आने देना चाहती हैं, उन्होंने ही श्री खड़गे के नाम को आगे बढ़ाकर ये बता दिया कि आने वाले लोकसभा चुनावों में इंडिया का नेतृत्व कांग्रेस ही मुख्य रूप से करेगी। गौरतलब है कि बैठक के लिए इससे पहले दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि इंडिया के प्रधानमंत्री उम्मीदवार का फैसला 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद किया जाएगा। इस सीधे बयान को जबरदस्ती तोड़–मरोड़ कर अन्य अर्थों में पेश किया जा रहा था। जबकि सुश्री बनर्जी और श्री खड़गे एक जैसी बात ही कह रहे हैं। दरअसल इस समय देश में जो राजनैतिक माहौल बन चुका है, उसमें इंडिया गठबंधन के सभी दलों को यह स्पष्ट हो चुका है कि उनके लिए एकजुट रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, बाकी सारी बातें दोयम हैं। यही बात अब देश की जनता को भी समझने की जरूरत है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साथ 151 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी की उपमा देते हैं, लेकिन आज उसी भारत में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जैसा नजारा बन चुका है। लोकतंत्र तभी जिंदा कहलाएगा, जब सत्ता पक्ष के साथ संसद में विपक्ष भी मौजूद हो। जब विपक्ष को सवाल पूछने और सत्ता से जवाब मांगने पर दंडित किया जाए। जब विपक्ष की गैरमौजूदगी में बिना चर्चा के महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर कानून बनाने का रास्ता तैयार हो जाए, तब हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है। संसद तक पहुंचा एक–एक प्रतिनिधि कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र के 15–20 लाख लोगों की आवाज बनता है। अब हिसाब लगा लीजिए कि 151 सांसदों को निलंबित कर एक झटके में कितने करोड़ लोगों की आवाज को मोदी सरकार ने खामोश करवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ वक्त से मेरे देशवासियों, मित्रो या भाइयो–बहनो की जगह मेरे परिवारजनो का संबोधन जनता को देते हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि अपने परिवार के करोड़ों लोगों की जुबान पर ताला लगवाकर आखिर कौन से परिवार धर्म का पालन किया जा रहा है। संसद का नया भवन जब उद्घाटित हुआ था तब श्री मोदी ने विपक्ष को मिलकर साथ चलने की नसीहत दी थी, रोना–धोना छोड़ने कहा था। उनके शब्दों के वास्तविक अर्थ शायद अब जाकर खुले हैं कि असल में प्रधानमंत्री विपक्ष को आगाह कर रहे थे कि संसद में बहस और चिंतन, सवाल और जवाब की परिपाटी पुराने भवन में ही स्मारक की तरह सजा दी गई है, नए भवन में यह सब नहीं होगा, केवल मन की बात होगी। जो कोई मन की बात सुनने से इंकार करेगा, उसे लोकतंत्र पर अच्छा लेक्चर सुनाकर बाहर कर दिया जाएगा। असल में संसद का नया भवन केवल नाम को ही संसद भवन रह गया है, इसे शायद आने वाली पीढ़ियां लोकतंत्र के मकबरे की तरह याद रखें। अगर हम देश की धड़कनों को सुनाने वाली संसद को मकबरे में तब्दील होते नहीं देखना चाहते हैं तो फिर हर हाल में लोकतंत्र की परिपाटियों को जिंदा रखना होगा। और इसके लिए केवल कुछ दलों पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है, बल्कि यह देश के हरेक नागरिक, हरेक संस्था, हरेक राजनैतिक दल का कर्तव्य है। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन के दल ही लोकतंत्र के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। क्या भाजपा के सभी नेता संसद में जो कुछ हुआ, उससे सहमत हैं। क्या बसपा, एआईएमआईएम, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, बीआरएस, बीजेडी जैसे तमाम दल अब भी लोकतंत्र का तमाशा बनते देख कर चुप रहेंगे। क्या कांग्रेस से उनकी अदावत लोकतंत्र और देश से भी बड़ी है। इन सवालों पर ईमानदारी से जवाब तलाशने होंगे, वर्ना आने वाली पीढ़ियां भारतीय लोकतंत्र को कहानियों में ही सुन पाएंगी।

डाटा चोर बनते युवा

इंटरनेट और डिजिटल युग में डाटा चोरी होना बहुत खतरनाक है। आज के समय में डाटा किसी हीरे–जवाहरात से कम नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग तक सब कुछ हमारे डाटा से चल रहा है। डाटा चोरी होने की खबरें हमें मिलती रहती हैं। डाटा लीक तब होता है जब अनधिकृत पार्टियों के हाथ संवेदनशील और गोपनीय डाटा लग जाता है। डाटा लीक होने से लोगों और संस्थानों को वित्तीय नुक्सान हो सकता है। साइबर अपराधी धवित्तीय डिटेल का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से धन चुराने, खरीदारी करने या अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। आजकल निजी जानध्कारियां, निजी मैसेज, फोटो और वीडियो लीक हो रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनियों पर आरोप लगते रहे हैं कि वे लोगों के व्यवहार से संबंधित डाटा इकट्ठा कर कंपनियों और राजनीतिक पार्टियों को बेचती हैं। पिछले चुनावों के दौरान कैम्ब्रिज एनालिटिका के डाटा का इस्तेमाल करने का आरोप कुछ नेताओं पर भी लगा था। भारत में इन विषयों पर गंभीर बातचीत इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि यहां का सामाजिक विज्ञान बुरी तरीके से मार्क्सवादी विचारधारा के असर में है। मार्क्सवादी स्कॉलर बिहेध्वियर साइंस यानि व्यवहारवादी विज्ञान को नहीं मानते। हमारे यहां इतिहास और महापुरुषों के बारे में पढ़ने पर काफी जोर है। इसके उलट व्यवहारवादी विज्ञान लोगों के व्यवहार (पसंद–नापसंद) के अध्ययन से यह देखने की कोशिश करता है कि लोग जैसा सोच रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लोगों के व्यवहार के बारे में मिले डेटा का इस्तेमाल कंपनियां अपना समान बेचने के प्रचार और विज्ञापनों में करती हैं और प्रोडक्ट में आवश्यक फेरबदल भी करती हैं। राजनीतिक पार्टियां इस डेटा का प्रयोग यह पता लगाने में करती हैं कि कौन सा सामाजिक समूह किस तरह का राजनीतिक व्यवहार करता है और उसे कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है ? अब तो भारत में डाटा चोरी करना युवाओं का खेल बन गया है। जल्दी से जल्दी या रात ही रात में धन कमाने की लालसा के चलते शिक्षित युवा भी हैकर्स बनते जा रहे हैं। इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के डाटा बैंक से 81 करोड़ भारतीयों का डाटा चोरी होने की खबरों से बवाल मचा था। भारतीय जांच एजेंसियों को करीब दो माह पहले इस डाटा के लीक होने और उसे डार्क वैब पर बेचे जाने का पता चला था। दिल्ली पुलिस ने तीन राज्यों से चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ के दौरान यह भी माना है कि उन्होंने अमेरिकी जांच एजेंसी फैडरल ब्यूरो ऑफ इनवैसटीगेशन और एक पड़ोसी देश के कम्प्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का डाटा भी चुराया है। पकडेध गए चार लोगों में एक ओडिशा का बी–टैक डिग्री धारक युवा है। दो लोग हरियाणा से हैं जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी है और एक व्यक्ति झांसी का है। खुफिया एजेंसी को जब डार्क वैब पर आधार और पासपोर्ट के रिकार्ड्स का डाटा मिला तब उन्होंने जांच को तेज किया। पकड़े गए चारों युवा एक गेमिंग प्लेटफार्म पर मिले थे। उसके बाद यह चारों दोस्त बन गए फिर इन्होंने जल्दी पैसा कमाने के लिए डाटा चुराकर बेचने का फैसला किया। इस पूरे मामले को और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (सीईआरटी–इन) को रिपोर्ट किया गया। ये एक नेशनल नोडल एजेंसी है जिसका काम हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर खतरों से निपटना है। इस एजेंसी ने डाटा की प्रामाणिकता जानने के लिए संबंधित विभागों से संपर्क साधा और उन्हें असली डाटा से मिलान करने को कहा। इन विभागों ने पाया कि करीब एक लाख लोगों का डाटा था। इसमें से 50 लोगों का डाटा लेकर उसे वैरीफाई किया गया जो कि असली निकला।" देश के कई राज्यों में कई युवाओं को डाटा चुराने के आरोप में पकड़ा गया है। आरोपियों के पास रक्षा कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, पैन कार्ड धारकों, छात्रों, डी मैट खाता धारकों, अमीर व्यक्तियों का डाटा और मोबाइल नंबर शामिल थ्थे। विदेशी हैकर्स ही नहीं जिस तेजी से भारत के युवा हैकर्स बन रहे हैं और तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यह प्रवृत्ति कोई अच्छी नहीं है। अब सवाल यह है कि सरकार कम्पनियों पर तो नकेल कस रही है डाटा सुरक्षित रखने के उपाय भी कर रही है लेकिन आईआईटी में दक्ष युवाओं को डाटा चोरी करने से कैसे रोका जाए और सर्वर में सेंध को कैसे रोका जाए, यह बहुत जरूरी है। डाटा को सुरक्षित बनाने के लिए इसके ईको सिस्टम को सुधारना होगा और डाटा सिक्योरिटी को पुख्ता बनाना ही होगा।

उपराष्ट्रपति की मिमिक्री और संसद की तुलना कोरियाई सदन से कर विपक्ष ने भारतीयों का दिल दुखाया

भारत की संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और हमारे देश के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक भी है। संसद भवन कोई इमारत मात्र नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला पवित्र स्थल भी है। संसद से हर भारतीय गहरा भावनात्मक लगाव रखता है लेकिन जिस तरह से संसद के कुछ सदस्य ही संसद की मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुँचा रहे हैं वह सचमुच आहत करने वाला है। देखा जाये तो विपक्ष के बड़े नेता विदेशी धरती पर जाकर तो भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाते ही हैं अब उन्होंने देश में भी संसदीय लोकतंत्र का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि अमर्यादित आचरण के चलते सदन से निलंबित किये गये विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद को ''संविधान की कब्रगाह'' बताते हुए इसकी तुलना उत्तर कोरियाई सदन से कर हर भारतीय का दिल दुखाया है। शिरोमणि अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल को संसद संविधान की कब्रगाह नजर आई तो दूसरी ओर तमाम तरह के आर्थिक अपराधों के आरोपों से घिरे कांग्रेस नेता और सांसद कार्ति चिदंबरम ने दावा कर दिया है कि संसद जल्द ही उत्तर कोरियाई सदन की तरह हो जाएगी। कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि हम उत्तर कोरियाई सदन की तरह बनने वाले हैं और केवल एक चीज की कमी है कि जब प्रधानमंत्री सदन के अंदर आएं तो सब साथ मिलकर तालियां बजाएं। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि यह एक सांकेतिक सदन बनने वाला है।

बात सिर्फ लोकतंत्र के अपमान की भी नहीं है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिस तरह मिमिक्री कर उनका अपमान करने की होड़ चल पड़ी है और हमारे संवैधानिक संस्थानों पर राजनीतिक हमले किये जाने का जो सिलसिला चला है वह एक तरह से भारत की छवि पर हमला है। कभी प्रधानमंत्री के लिए तानाशाह, हिटलर, नीच या कोई अन्य अपमानजनक शब्द उपयोग किया जाता है तो कभी देश की राष्ट्रपति का अपमान कर दिया जाता है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिस तरह अपमान किया गया उसने सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। यहां यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि राष्ट्रपति द्रौपद्री मुर्मू हों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों...यह सभी साधारण और गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन सभी को राजनीति विरासत में नहीं मिली बल्कि यह जीवन में अभाव और संघर्षों पर विजय हासिल करते हुए यहां तक पहुँचे हैं लेकिन लगता है कि दिल्ली पर दशकों तक राज करने वाले राज परिवार के लोगों को यह सब भा नहीं रहा इसलिए सुनियोजित तरीके से शीर्ष पदों पर बैठे लोगों पर हमले किये और करवाये जा रहे हैं।

विपक्ष ने ऐसा ही रवैया न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थानों के प्रति भी अपनाया हुआ है। कोई फैसला अपने मन मुताबिक नहीं आये तो न्यायपालिका पर सवाल उठा देना, चुनाव हार गये तो ईवीएम पर सवाल उठा देना, नोटिस मिल जाये तो आयकर विभाग या ईडी पर सवाल उठा देना और पूछताछ के लिए बुला लिया जाये तो सीबीआई पर राजनीतिक हमला कर देना अब विपक्षी नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और जनता की अदालत हर चुनाव में त्वरित न्याय करती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति से सहानुभूति जताते हुए जो कुछ कहा है वह मात्र उनके समर्थन में खड़ा होना नहीं है बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शब्दों से उनके मन की पीड़ा और चिंता की भी झलक मिलती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति को जिस तरह अपमानित किया गया, उससे वह बेहद व्यथित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शालीन तथा मर्यादा के दायरे में होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारी संसदीय परंपराएं हैं जिन पर हमें गर्व है और हम उन्हें बरकरार रखने की आशा करते हैं।

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन कर संसद परिसर में कुछ सांसदों की ओर से 'अशोभनीय आचरण' करते हुए उनका मजाक उड़ाए जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बारे में उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट में

पूर्वांचल विवि को नैक मूल्यांकन में 'ए प्लस' ग्रेड मिलने से राज्यपाल आनंदीबेन खुश, दी बधाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा किए गए निरीक्षण एवं मूल्यांकन में 'ए

प्लस' ग्रेड प्राप्त होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ज्ञातव्य है कि नैक मूल्यांकन में 'ए प्लस प्लस' सर्वोच्च ग्रेड है और 'ए प्लस' का शुमार भी उच्चतम ग्रेड में ही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने अपने प्रयासों में सर्वोच्च ग्रेड से मात्र '0.22' अंकों से ही पीछे रहते हुए ये उच्चतम ग्रेड प्राप्त किया है। नैक के उच्चतम ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालयों में शुमार होने के साथ ही वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय देश के प्रमुख शीर्ष संस्थानों में भी शामिल हो गया है।इससे पूर्व विश्वविद्यालय वर्ष 2004 में नैक का ''बी ग्रेड तथा वर्ष 2016 में नैक का ''बी प्लसश्श ग्रेड प्राप्त कर चुका है और अब तीसरी बार के मूल्यांकन में सर्वोच्च ग्रेड के निकटतम सीजीपीए हासिल करते हुए ए प्लसश् ग्रेड प्राप्त किया है। बी प्लस ग्रेड से 'ए प्लस' ग्रेड तक के इस सफर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा निरंतर मार्गदर्शन, अनवरत समीक्षा बैठकों के माध्यम से विश्वविद्यालय में अकादमिक एवं व्यवस्थागत सुधार कराते हुए नैक के लिये प्रस्तुत की जाने वाली सेल्फ स्टडी रिपोर्ट को बेहतर कराने के लिये युद्धस्तर पर कार्य करने के साथ–साथ इस कार्य में लगे प्राध्यापकों तथा अन्य सदस्यों को भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने विश्वविद्यालय की नैक टीम को हर बिन्दु पर शत–प्रतिशत् तैयारी के लिए जोर देते हुए कड़ी मेहनत के साथ सुधार करते हुए प्रत्येक मानक को अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता पर ले जाने के लिए मार्ग दर्शन भी किया। निरंतर कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरुप आज विश्वविद्यालय को ये उपलब्धि हासिल हो सकी है। इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए राज्यपाल ने प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकनों में प्राप्त हो रही उल्लेखनीय सफलताओं पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों को ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होने से प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के लिए प्रदेश और देश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के उन विद्यार्थियों को होगा जो आर्थिक कारणों से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं।

यूपी में 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है चुनाव, इंडिया गठबंधन 31 दिसंबर को लेगा फैसला

लखनऊ। मंगलवार को नयी दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता शामिल हुए। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर वार्ता हुई। पाटी सूत्रों की मानें तो प्रदेश में संगठन के पदाअधिकारी ही सीट बंटवारे को लेकर फैसला लेगें। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर अपना प्रतिनिधि तय करेगी। वहीं नेताओं का कहना है कि सपा और कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर कोई गतिरोध पैदा होगा तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व दखलंदाजी करेगा। यूपी में सीटों के बंटवारे पर अब इंडिया गठबंधन 31 दिसंबर को लेगा फैसला करेगा। पार्टी सूत्रों की मानें तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी 15–20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही सीट बंटवारे पर फैसला लेगी। आप को बता दें कि नए दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की आज यहां हुई चौथी बैठक में इन पाटियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन–ईवीएम मतदान प्रणाली पर फिर सवाल उठाए और चुनाव आयोग से इसमे सुधार का सुझाव देने को लेकर आयोग से मिलने का समय भी मांगा। गठबंधन ने कहा कि ईवीएम की कार्य प्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह है और कई विशेषज्ञ और प्रोफेशनल ने भी इसको लेकर सवाल किए हैं। गठबंधन के नेताओं ने कहा कि ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को भी एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया लेकिन आयोग ने इस ज्ञापन पर गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई। विपक्षी दलों ने कहा ''हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने हुए विकल्प को सत्यापित करने के बाद उसे एक अलग मत पेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट की 100 प्रतिशत गणना की जानी चाहिए। ऐसा करने से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर लोगों का पूर्ण विश्वास बहाल होगा। गौरतलब है कि विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की आज यहां अशोका होटल में बैठक हुई जिसमें विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने और उसके बाद गठबंधन की 8 से 10 जनसभाएं करने का फैसला लिया गया।

वेतन कटौती को लेकर केजीएमयू में आउटसोर्सिंग कर्मचारी की हड़ताल

लखनऊ। लखनऊ के केजीएमयू में संविदा कर्मियों ने वेतन कटौती को लेकर हड़ताल कर दी। जिसके बाद OPD से लेकर इमरजेंसी तक में पर्चा बनना बंद हो गया और मरीजों को इलाज मिलना ठप हो गया। बुधवार को सुबह करीब डेढ़ हजार संविदा कर्मी पूर्व निर्धारित तरीके से हड़ताल पर चले गए। कर्मियों का आरोप हैं कि नए कुलपति के आने के बाद से उनकी सेवा प्रदाता कंपनी में वेतन में कटौती करनी शुरू कर दी। अब एक महीने में मिलने वाले 4 साप्ताहिक अवकाश के लिए भी वेतन कटौती हो रही हैं। इसके अलावा सरकारी अवकाश के दिन का वेतन भी काट लिया जाता हैं। संविदा कर्मियों का आरोप हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार इस कटौती को लेकर बताया गया पर इस मामले की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही थी। अब जब सुनवाई नही हुई तो कर्मियों को मजबूरी में कार्य विरत होना पड़ रहा हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने कुलपति कार्यालय का घेराव करते हुए तत्काल विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मामले में एक्शन लेने की मांग की।

अज्ञात कारणों से बिजली मैकेनिक की मौत, साथी गंभीर

बांदा। जिले के अतर्रा कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते बिजली मैकेनिक की दर्दनाक मौत गई। वहीं, उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। राहगीरों की सूचना पर चौकीदार रज्जू ने थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पड़े दीपू को सीएचसी भेज दिया। यहां हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल और उसके बाद कानपुर हैलट रेफर कर दिया गया, जहां उपचार चल रहा है। वहीं, मृतक बसंत को ट्रामा सेंटर के बाद मोर्चरी हाउस भेजा गया है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मजरा समूह का पुरवा निवासी मृतक बसंत कुमार (29) पुत्र छेदीलाल कुशवाहा अपनी बाइक से मित्र दीपू पुत्र धर्मपाल निवासी कुटुरवा का पुरवा मंगलवार की देर शाम घर वापस लौटते समय गुमाई माइनर नंबर एक रोड पर लहूलुहान हालत पर पड़े हुए थे। कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि किसी वाहन की चपेट में आने या स्वयं से टकरा जाने के बाद हादसा हुआ है। मृतक के परिजनों की ओर से तहरीर मिलते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि मृतक बसंत कुमार (बसंता) तीन भाइयों में सबसे छोटा था। घटना से परिजनों को रो–रोकर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों ने थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया घटनास्थल से महज दो किलोमीटर की दूरी पर परिवार रहता था, लेकिन थाना पुलिस ने मृतक बसंत कुमार को बिना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर के दिखाए ही प्राइवेट डग्गा में लादकर जानवरों की तरह जिला अस्पताल मोर्चरी हाउस में रख दिया। वहीं, मृतक के चचेरे साले नरैनी निवासी राम प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि साजिश के तहत मेरे दामाद की हत्या की गई है। दामाद का फोन भी गायब है। दीपू के परिजनों ने सारे नंबर डिलीट कर दिए हैं और घायल को ले गए हैं। मृतक बसंत कुमार के परिजनों को भी कोई खबर नहीं की गई थी।

कोर्ट के आदेश पर 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उरई/जालौन। जालौन में स्पेशल जज डकैती कोर्ट के आदेश पर 13 लोगों के खिलाफ जालसाजी कर जमीन हड़पने का मुकदमा उरई कोतवाली में दर्ज किया गया है। इस मामले में तीन सगी बहनों के साथ–साथ कालपी के सपा विधायक के पुत्र और उरई नगर पालिका की अध्यक्ष के नाती नाम शामिल है। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का है। उरई कोतवाली क्षेत्र के नया रामनगर के रहने वाले विवेक चौरसिया पुत्र मुन्ना लाल चौरसिया ने स्पेशल जज डकैती कोर्ट में वाद दायर करते हुए बताया कि प्रार्थी व उसके परिजन के लोगों के साथ अरविंद बंसल पुत्र हरिशंकर बंसल के काफी पुराने वैश्यवासिक और पारिवारिक संबंध चल आ रहे थे। उरई नगर पालिका के अंदर दोनों लोगों की खतौनी फसली सन 1426 से 1431 के गाटा संख्या 31 के खसरा संख्या 1377/2 के रखवा 0.186 हेक्टेयर, 1385/2 रकवा 0.2950 हेक्टेयर के संक्रमणीय भूमिधर व मकान 22 नया 64 के वर्ष 1977 के पूर्व से मलिक व काबिज चले आ रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर उरई कोतवाली पुलिस ने कालपी के सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी के बेटे आशीष चतुर्वेदी, पालिकाध्यक्ष के नाती राहुल चौधरी, शोभा गोयल, सुनीता बंसल, सपा नेता जुल्फिकार अहमद, जमाल अहमद उर्फ पप्पू, अब्दुल जलील, विवेक गोयल, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, राजनाथ त्रिवेदी, पंकज कुमार, सत्येंद्र श्रीवास्तव व नरेंद्र वर्मा पर संपत्ति हड़पने के मामले में धारा 420 के अलावा सात अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। सीओ सिटी गिरजाशंकर त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दर्ज की गई है, निष्पक्ष जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

तीन दिवसीय विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव कल से

ड्राइंग, गायन, नृत्य, वाद्ययंत्र, स्पीच और कबाड़ से जुगाड़ आदि क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखायेंगे छात्र

लखनऊ। छात्र–छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिये तीन दिवसीय विद्यार्थी

प्रतिमा उत्सव आगामी 22 दिसम्बर से एनआरएलसी ट्रेनिंग संस्थान, सेक्टर–जी, जानकीपुरम के ऑडिटोरियम में शुरू हो रहा है। सामाजिक संस्था सोसायटी ऑफ कॅरियर टेक्नोलॉजी (सोक्ट) एवं जन विकास महासभा, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में शुरू हो रहे इस उत्सव का उद्घाटन प्रातः 11 बजे होगा, जबकि समापन कार्यक्रम 24 दिसम्बर को अपराह्न दो बजे होगा। उत्सव के मुख्य आयोजक पंकज तिवारी ने बताया कि उत्सव की शुरूआत प्रातः दस बजे शंखनाद व मंत्रोच्चारण के साथ होगी। इसके उपरान्त विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी आर्ट, ड्राइंग, गायन, नृत्य, वाद्ययंत्र, स्पीच और कबाड़ से जुगाड़ आदि क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे, जो अगले दिन 23 दिसम्बर प्रातः दस बजे से साढ़े चार बजे और 24 दिसम्बर प्रातः दस बजे से दोपहर एक बजे के बीच जारी रहेगी। उत्सव का समापन 24 दिसम्बर को अपराह्न दो बजे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, आत्मनिर्भर भारत एवं सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों को सम्मानित करने के साथ किया जायेगा। मुख्य आयोजक पंकज तिवारी ने बताया कि तीन दिनों तक चलने वाले इस उत्सव कार्यक्रम के दौरान पौधरोपण, पर्यावरण एवं जल संरक्षण संकल्प, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन, आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जागरूकता, नशामुक्त समाज का संकल्प दिलाने आदि पर भी कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है, ताकि छात्रों को बेहतर जीवन बनाने के साथ अपना कॅरियर बनाने में मार्गदर्शन मिल सके।

पासी समाज की धरोहरों के संरक्षण पर ध्यान नहीं

22 को महाराजा बिजली पासी के जन्मोत्सव पर उठेंगी मांगें–आर ए प्रसाद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पासियों की आबादी करीब एक करोड़ है। सैकड़ो विधानसभाओं में पासियों का निर्णायक मत होता है फिर भी सरकार और नेताओं द्वारा पासी समाज की उपेक्षा की जाती है। पासी समाज की धरोहरों के संरक्षण पर ध्यान नहीं है। अखिल भारतीय पासी समाज केराष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईएएस आरए प्रसाद ने बताया कि इन सब समस्याओं और मांगों को लेकर 22 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी के जन्मोत्सव के अवसर पर महाराजा बिजली पासी के किला आशियाना लखनऊ में पासी समाज अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ परिक्षेत्र पर महाराजा बिजली पासी का राज्य वर्ष 1160 से वर्ष 1200 तक था। महाराजा बिजली पासी के बारह किले थे। इनमें मात्र एक किले की बाउन्ड्री बन पायी है। शेष ग्यारह किलों पर अवैध कब्जा हो गया है। महाराजा बिजली पासी के किलों का ऐतिहासिक महत्व है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि महाराजा बिजली पासी के ग्यारह किलों से अवैध कब्जा हटाकर इनका सौन्दर्यीकरण कराया जाये। लखनऊ को पासी सम्राटलाखन पासी यानि लखना पासी ने बसाया था। राजा लाखन पासी का राज्य वर्ष 11वीं शताब्दी में था। राजा लाखन पासी का किला वर्तमान लखनऊ मेडिकल कालेज और टीले वाली मस्जिद के पास था। महाराजा लाखन पासी की विशाल मूर्ति मेडिकल कालेज और टीले वाली मस्जिद के बीच मेन रोड के चौराहे पर शीघ्रातिशीघ्र लगायी जाये। इसके अलावा महाराजा लाखन पासी के ऊपर डाक टिकट जारी किया जाये। दिनेश शर्मा जब लखनऊ के मेयर थे, तब कार्यक्रम में कहा था कि नगर महापालिका लखनऊ ने नदी के किनारे लाखन वाटिका बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। उन्होंने यह वादा किया था कि सरकार बनते ही वे इस लाखन वाटिका की मांग पूरी करवा देंगे,लेकिन यह कार्य रुका पड़ा है। लखनऊ पर जब वाजिद अली शाह का राज था, तब 1857 में अंग्रेजी सरकार ने इस पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी थी। अंग्रेजी हमलों का मुकाबला देशी फौजों ने किया। स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई में पासी समाज की शिरमौर एवं वीर योद्धा वीरांगना ऊदादेवी पासी ने सिकन्दरबाग चौराहे के पास बोटोनिकल के प्रांगण में स्थित एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गयीं और उन्होंने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में वे भी शहीद हो गयी थीं। ऐसी बहादुर महिला की बहादुरी की कहानी पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जानी चाहिए ताकि बच्चों में देश के प्रति समर्पण बढ़े। इसके अलावा वीरांगना ऊदादेवी पासी के नाम पर शिक्षण संस्थानों का नामकरण भी किया जाये। राजा सुहेलदेव की स्मृति में उनका भव्य स्मृति भवन बनाया जाये। 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक अवध प्रान्त के बड़े भू–भाग पर लम्बे अरसे तक पासियों का कब्जा रहा। हमारी मांग है कि पासियों का इतिहास लिखवाया जाये, ताकि उनके पंचायती राज का लाभ उठाया जा सके।बिहार सरकार ने नशाबन्दी लागू किया लेकिन सरकार ने ताड़ी को शराब के समकक्ष कर दिया है। ताड़ी पासियों का पुश्तैनी पेशा है। इस कानून के कारण आज बिहार में हजारों पासी जेलों में बन्द हैं। सरकार से आग्रह है कि ताड़ी को समकक्ष बनाने वाले काले कानून को तत्काल समाप्त किया जाये। बख्शी का तालाब तहसील की ग्रामसभा पट्टी ढिलवासी में राजा टीकन नाथ पासी के किले के अवशेष हैं। हमने सरकार से आग्रह किया था कि इस किले के ट्रस्ट द्वारा हाई स्कूल ,इन्टर कालेज खोलने के लिए निःशुल्क जमीन देने का प्रस्ताव किया था। शासन के कुछ नुमाइन्दों ने जमीन की नाप–जोख कराया था। लेकिन, पता नहीं क्यों आगे का काम रुक गया है। यह मांगें अखिल भारतीय पासी समाज के द्वारा 22 दिसम्बर 2023 को लखनऊ के आशियाना में महाराजा बिजली पासी के किले पर आयोजित महाराजा बिजली पासी जन्मोत्सव कार्यक्रम में समस्त भारत से पधारे पासियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। अपनी माँगों के समर्थन में फरवरी 2024 में दिल्ली में धरना दिया जायेगा।

विन्ध्यवासिनी मंदिर के समीप गंगा के किनारे पक्का स्नान घाट एवं बुनियादी सुविधाओं के लिए 48 करोड़ स्वीकृत

प्रथम किश्त के रूप में 5.50 करोड़ रूपये जारी–जयवीर

लखनऊ। प्रदेश का पर्यटन विभाग मीरजापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध मां विध्यवासिनी देवी मंदिर के समीप गंगा किनारे पक्का स्नान घाट और पाथवे बनाएगा। इसके लिए करीब 48 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रथम किश्त के रूप में 5.50 करोड़ रुपये जारी किए गये हैं। ये सारे कार्य पूरे होने के बाद श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस धाम की महिमा का वर्णन मारकंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण के साथ–साथ विभिन्न धार्मिक गंथों में वर्णित है। मां विध्यवासिनी के दरबार में दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, मध्यप्रदेश समेत देश के कई अन्य हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा यह पावन धाम मुंडन संस्कार के लिए सुविख्यात है। यहां दूर–दूर से लोग बच्चों के मुंडन के लिए आते हैं। मीरजापुर में स्थित माता के धाम से उत्तर दिशा में मां गंगा प्रवाहित होती हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से नदी के किनारे पक्का स्नान घाट और पाथवे का निर्माण कराया जायेगा। चेंजिंग रूम, छतरी, ट्वयालट ब्लाक, काफर डैम और जलनिकासी समेत कई और कार्य कराए जाएंगे। यूपी में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में यहां 31 करोड़ 85 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे। यह संख्या 2021 से करीब 180 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले वर्ष विंध्याचल में 47 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे। इस तरह प्रदेश के पर्यटन में विंध्याचल का बड़ा योगदान है। पर्यटक सुविधाओं पर सरकार का विशेष जोर है। मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन–पूजन के लिए दूर–दूर से श्रद्धालु आते हैं। पक्का स्नान घाट और पाथवे बनने के बाद लोगों को काफी सुविधा होगी।

अब सत्यापन के बाद ही बनेगा 18 साल से अधिक आयु के लोगों का आधार

आधार के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति अनिवार्य

लखनऊ। अब सत्यापन के बाद ही 18 साल से अधिक आयु के निवासियों का आधारकार्ड बनेगा। अब राज्य सरकार की अनुमति के बाद वयस्क लोगों के आधार कार्ड बनाए जा सकेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर और सब–डिवीजन स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी को और सब–डिवीजन स्तर पर एसडीएम को नामित किया गया है। इनके द्वारा सत्यापन के बाद ही 18 साल से अधिक आयु के लोगों का आधार कार्ड बन सकेगा। इसके लिये अब पासपोर्ट की तरह सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए आधार नामांकन की सुविधा कुछ चुने हुए आधार केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी। जिसमें मुख्य रूप से प्रत्येक जिले का मुख्य डाक घर, उप डाक घर और प्राधिकरण द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र शामिल है जिनकी संख्या 1136 है। इन केंद्रों पर आधार नामांकन के उपरांत सूचना प्राधि

करण को भेज दी जाएगी जहां डेटा क्वालिटी जांच के उपरांत आवेदन को सर्विस प्लस पोर्टल पर सत्यापन के लिए भेज दिया जाएगा। सर्विस पोर्टल पर आने वाले आवेदन का सत्यापन एसडीएम अपने स्तर पर करवाएंगे। इसमें लगाए गए सभी दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अगर सब सही पाया जाता है तो आधार जारी करने की अनुमति दे देंगे जिसके बाद 180 दिनों के अंदर आधार बन जाएगा। अगर सूचना संदिग्ध होगी तो नोडल अधिकारी इसे रिजेक्ट कर देंगे। उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि ये दिशा निर्देश 18 साल से अधिक वर्ष के उन निवासियों के लिए है जो पहली बार अपना आधार बनवा रहे है। एक बार आधार बन जाने के बाद वे भी सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत अपना आधार अपडेट करवा सकते है किसी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे सभी निवासी जिनके आधार पहले से बने है वे अपने आधार में सुधार,अपडेट आसानी से करवा सकते है ऐसे लोगों को इस नई व्यवस्था से नहीं गुजरना पड़ेगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 14,095 आधार नामांकन और अपडेट मशीनों के माध्यम से आधार नामांकन और अपडेट का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 10,408 मशीनों पर आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।

गैर इरादतन हत्या में 10 साल की कैद,शराब पीने के दौरान 2009 में हुई थी मारपीट

अलीगढ़। जिले के बरला थाना क्षेत्र में 2009 में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि दोषी ने मृतक के साथ बुरी तरह से मारपीट की थी। मारपीट के दौरान मृतक के गंभीर चोंटे आई थी और अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद पीड़ित के भाई ने बरला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में चार्जशीट पेश की थी और मामले का ट्रायल चल रहा था। एडीजे–14 अमित कुमार तिवारी ने दोषी को सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण मुरारी जौहरी ने बताया कि अतरौली निवासी सोरन सिंह पुत्र बाबूलाल ने 29 अक्टूबर 2009 को बरला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने बताया था कि उसके भाई घनश्याम उर्फ पप्पू ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। 28 अक्टूबर की रात को उसका भाई भट्ठे पर मानपाल पुत्र राकेश के साथ शराब पी रहा था।

शराब पीने के दौरान दोनों में विवाद हो गया था। जिसके बाद मानपाल ने घनश्याम को लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया और फावड़े की बट से भी मारा। जिससे घनश्याम के गंभीर चोटें आई थी और अस्पताल जाने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बरला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया था। इसके बाद न्यायालय में लगातार इसका ट्रायल चला और अब इसमें फैसला आया है। एडीजीसी ने बताया कि आरोपी मानपाल पुत्र राकेश को न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आर्थिक दंड न चुकाने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय के फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

दो दिन बाद भी नहीं बदले गए टूटे खंभे, अंधेरे में बिजली उपभोक्ता

बस्ती। विद्युत उपकेंद्र बघौडी क्षेत्र के बजहिया गांव मे दो दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। 17 दिसंबर दिन को एक ट्रक में एबी केबल फंसने से सात खंभे टूटकर गिर गए थे। टूटे खंभों को न तो हटवाया गया और न ही उनकी जगह दूसरे खंभे लगाए गए हैं। बघौड़ी उपकेंद्र से टिनिच फीडर को बिजली आपूर्ति दी जाती है। इसी फीडर पर बजहिया गांव स्थिति है। टूटी लाइन से करीब 55 उपभोक्ताओं के परिसर को बिजली मिलती है। गांव के गुड्डू, गया प्रसाद, सूरज आदि ने बताया कि टूटे खंभों को बदलने का काम शुरू नहीं हो पाया है। अवर अभियंता अनुज कुमार कन्नौजिया ने बताया कि ठेकेदार को टूटे खंभे बदलने के निर्देश दिए गए हैं। लाइन दुरुस्त करने में दो दिन लग जाएगा।

स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में जा रही बोलेरो बस से टकराई,6 छात्रा हुए घायल

बहराइच। जिले के मिहीपुरवा–बिछिया मार्ग पर यात्रियों से भरी तेज रफ्तार में निजी बस चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। पीछे से आ रही एक बोलेरो अनियंत्रित होकर बस में भिड़ गई। बोलेरो वाहन में सवार 6 दर्जन छात्राएं घायल हो गई। यह सभी छात्राएं स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने बहराइच जिला उद्योग कार्यालय जा रही थीं। मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के मिहीपुरवा–बिछिया मार्ग पर बेलछा वन बैरियर के पास बुधवार सुबह प्राइवेट बस और पीछे से आ रहे बोलेरो की टक्कर हो गई। बिछिया से बहराइच जा रही प्राइवेट बस चालक द्वारा तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रही बोलेरो अनियंत्रित होकर बस में भिड़ गई। हादसे में बोलेरो वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में बोलेरो चालक समेत उसमें

सवार 6 छात्राएं घायल हो गई। दुर्घटना के बाद बस मौके से फरार हो गई। बोलेरो से यात्रा कर रहे पवन कुमार ने बताया कि वह सुजौली क्षेत्र के जयश्री पुरवा बड़खडिया के रहने वाले हैं। पवन ने बताया उनके आसपास गांव की 6 छात्राएं पूजा, अंशिका, रीमा, पूनम, चिंता, रंजू व सशी स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में स्मार्टफोन लेने के लिए बहराइच जिला उद्योग कार्यालय जा रही थी। घटना की सूचना छात्राओं ने कोतवाली पुलिस को दी है।

शिक्षकों के दो गुट आए आमने-सामने,एक गुट ने निर्वाचित पदाधिकारियों को बताया फर्जी

उरई/जालौन। जालौन में पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर शिक्षकों के दो गुट आमने सामने आ गए हैं। शिक्षक संघ के एक गुट के शिक्षक नेता अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित बता रहे हैं, वहीं दूसरा गुट इस निर्वाचन प्रक्रिया पर ही उंगली उठाते हुए चुनाव प्रक्रिया को पूर्णतः फर्जी बता रहा है।

मंगलवार शाम को जालौन के जिला मुख्यालय उरई में शिक्षक नेता राजीव कुमार त्रिपाठी ने माध्यमिक शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के चुनाव में जो लोग अपने आपको निर्विरोध निर्वाचित बता रहे हैं, वह पूर्णतया फर्जी है। उन्होंने बताया कि उनके विरोधी अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों द्वारा जो आपत्तियां दर्ज की गई थी, वह आपत्तियां संविधान में ही दर्ज नहीं हैं और न ही निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा जारी चुनावी कार्यक्रम में ऐसा कोई नियम दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो लोग खुद को पदाधिकारी बता रहे हैं, वह लोग संगठन के कभी सदस्य ही नहीं रहे हैं। इसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य हैं। जब उक्त बातें पर्यवेक्षकों को बताई गई तो पर्यवेक्षकों द्वारा उनकी बातों को नकार दिया गया तथा रात्रि आठ बजे विरोधियों के पर्चे को वैध करार कर दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना मतदाता सूची के चुनाव कराया गया है।

सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक,खेत में पानी लगाते समय डसा, डिब्बे में कैद करके ले गया साथ

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कोबरा सांप ने 13 वर्षीय किशोर को काट लिया, जिसके बाद किशोर ने उस सांप को पकड़ लिया और सीधे अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में उसने डॉक्टर को बताया कि इसी सांप ने मुझे का है। सांप को देखते ही डॉक्टर्स के होश उड़ गए। फिलहाल, किशोर का इलाज चल रहा है। पूरा मामला बांदा के मटौंधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आलमखोर गांव का है, जहां के रहने वाले योगेंद्र अपने खेत में पर पानी लगाने गया हुआ था। अचानक वहां उन्हें जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वहीं परिजनों ने उससे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। योगेंद्र ने उस सांप को पकड़कर डिब्बे में भर लिया और उसे लेकर सीधे अस्पताल पहुंच गया, जहां पर सांप देखने वालों की भीड़ लग गई। मामले में जिला अस्पताल के म्डव डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि एक योगेश नाम के युवक को लाया गया था, जिसे किसी जहरीले सांप ने काटा है। भर्ती करके उसका उपचार किया जा रहा है। वह अपने साथ सांप भी लाया था, जो काले रंग का है। उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।

ऊर्जा राज्य मंत्री डा सोमेंद्र तोमर ने किया राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के अधिवेशन का उद्घाटन

लखनऊ। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के 76 में वार्षिक महा अधिवेशन का भव्य उद्घाटन ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर द्वारा किया गया। संगठन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर ने कहा कि विद्युत अभियंताओं की कार्यकुशलता एवं मेहनत की बदौलत प्रदेश उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी अभियंताओं एवं ऊर्जा परिवार को मिलकर हमें इस प्रकार का कार्य करना चाहिए की उपभोक्ताओं का विश्वास विद्युत अभियंताओं के प्रति और बढ़े। ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा संगठन प्रतिनिधियों के प्रति माह बैठक कर बेहतर उपभोक्ता सेवा और मांगो व समस्याओं पर चर्चा उनका समाधान किया जायेगा। महाधिवेशन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत अभियंताओं ने प्रतिभाग किया तथा बेहतर उपभोकता सेवा हेतु प्रस्ताव और संवर्ग की समस्याओं पर चर्चा की गई। अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया जिसमें विशेष रूप से आल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई आर के त्रिवेदी,महासचिव इं अभिमन्यु धनकर, आल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर के सलाहकार ई सुधीर पवार,डिप्लोमा महासंघ उत्तर प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ई एच के मिश्र, महासचिव ई नितिन श्रीवास्तव ने प्रदेशभर से आए जूनियर इंजीनियर एवम प्रोन्नत अभियंताओं को महाधिवेशन शुभकामनाएं दी।

स्वयं के लिए मोक्स की तैयारी पर व्याख्यान और चर्चा सत्र का आयोजन

अलीगढ़। एएमयू के जेएनएमसी सभागार में एसडब्ल्यूआईएम के समन्वयक प्रोफेसर आसिम जफर की देखरेख में 'स्वंय के लिए मोक्स की तैयारी' पर एक व्याख्यान और चर्चा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 150 शिक्षकों ने भाग लिया। स्वंय के राष्ट्रीय समन्वयक, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एंड्रयू थंगराज ने व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओसी) के विकास, शिक्षण रणनीतियों, तकनीकी नवाचारों और उनके प्रभाव पर एक व्यापक व्याख्यान दिया। एनपीटीईएल की सीओओ भारती बालाजी ने एनपीटीईएल और स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी प्रदान की और प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए। प्रोफेसर आसिम जफर ने मॉक के महत्व को समझाते हुए सत्र की शुरुआत की और एएमयू के मॉक पाठ्यक्रमों के बारे में बताया। व्यापक शिक्षा में स्वयं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि एएमयू एक ऐसा संस्थान है जो बड़े पैमाने पर छात्रों को तैयार करने की क्षमता रखता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डीन और विभागाध्यक्षों सहित 20 वरिष्ठ शिक्षक पहले ही अपनी रुचि व्यक्त कर चुके हैं और एमओसी तैयार करने के लिए मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं। प्रो. एम. सालिम बेग की अध्यक्षता में आयोजित सत्र में मॉक तैयारी के लिए विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं की सराहना की गई। प्रोफेसर बेग ने इस बात पर जोर दिया कि मॉक की तैयारी विभिन्न रैंकिंग रूपरेखाओं का एक अभिन्न अंग है, जो एएमयू की रैंकिंग पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि एएमयू शिक्षक जुलाई 2024 से शुरू होने वाले अगले सेमेस्टर में पाठ्यक्रम तैयार करेंगे और शुरू करेंगे। प्रो. एम. शाहिद नईम ने शिक्षकों और संस्थान दोनों के लिए बेहतर परिणाम की उम्मीद करते हुए एमओसीएस की तैयारी में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया। यूजीसीएचआरडीसी के निदेशक डॉ. फायजा अब्बासी ने कहा कि स्वयम पर मोक्स पेश करने से शिक्षकों और विश्वविद्यालय दोनों को फायदा होगा। उन्होंने सत्र का संचालन किया और धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

जर्मन अभिनेत्री सुजैन बर्नेट ने एस. टी एस. स्कूल (मिंटो सर्किल) का भ्रमण किया

अलीगढ़। जर्मन अभिनेत्री सुश्री सुजैन बर्नेट ने एस. टी एस. स्कूल (मिंटो सर्किल) ए.एम.यू. अलीगढ़ का गत दिवस को भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने छात्र्रों एंव शिक्षकों से मुलाकात की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य फैसल नफीस ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। भ्रमण के दौरान उनके साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य और अन्य शिक्षक भी उपस्थित रहे। अपने भ्रमण के दौरान सुजैन बर्नेट विद्यालय की ऐतिहासिक इमारत को देखकर बहुत प्रभावित हुंइ और उन्होंने इसकी खूब प्रंशसा की। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मे उनकी गहरी रुचि रही हैं। अपने भ्रमण के दौरान वह यहाँ की तहजीब व तालीम से बहुत प्रभावित हुई हैं और भविष्य मे वह विद्यालय के भ्रमण के लिए दोबारा अवश्य आयेंगी। सुजैन बर्नेट ने विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्मों में अभिनय किया है और उन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइममिनिस्टर (2019) में सोनिया गाँधी जी का किरदार निभाया है। इसके अतिरिक्त कलर्स (टीवी चौनेल) के ऐतिहासिक धारावाहिक चक्रवर्ती अशोक सम्राट, स्टार प्लस के धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है आदि में भी उन्होंने अभिनय किया है।

काशी के फूलों की खुशबू विदेशों में बिखरेंगी,खाड़ी देश भेजा गया गुलाब का फूल

वाराणसी। काशी के किसानों के बागों में खिलने वाले फूलों की खुशबू विदेशों तक पहुंच रही है। फल और सब्जियों के बाद अब वाराणसी से पहली बार गुलाब के फूल खाड़ी देश को भेजे गए है। फूलों के साथ मटर की खेप और गन्ने का सैंपल भी भेजा गया है। 3.5 मीट्रिक टन कृषि उत्पाद वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट से गल्फ देशों को निर्यात किया गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के चेयरमैन अभिषेक देव ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। गौरतलब है कि इसी महीने गेंदे के फूल का निर्यात भी संयुक्त अरब अमीरात को वाराणसी से किया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023–24 में अब तक 598 मीट्रिक टन फल, सब्जी और फूलों का निर्यात हुआ है। एपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव ने बताया कि यूपी वित्त वर्ष 2022–23 में 18991.43 करोड़ रुपए के साथ पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य था। लेकिन 2023–24 में सिर्फ 8 महीने में 10620 करोड़ का कृषि निर्यात कर यूपी तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। बताते चलें कि निर्यात के लिए पहले स्थान पर गुजरात और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हैं। यूपी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए स्वदेशी और जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों को निर्यात करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिसके तहत विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद जैसे हरी मिर्च, लगड़ा आम, भिंडी, आलू, सिंघाड़ा, केला, कुंदरू, लौकी, परवल के साथ, गेंदे का फूल ,गुलाब के फूल को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया गया है।

माध्यमिक विद्यालयो में 2014 के बाद नियुक्त शिक्षको को नहीं मिलेगा जीवन बीमा योजना का लाभ

जारी हुआ शासनादेश,माध्यमिक शिक्षक संघ और तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति ने जताई नाखुशी

लखनऊ। प्रदेश में सहायता प्राप्त यानि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को अनिवार्य जीवन बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शासन ने एडेड कॉलेजों के कर्मचारियों के लिए लाभत्रयी नियमावली में संशोधन संबंधित आदेश जारी किया है। इससे प्रदेश भर के 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों के 10 हजार से अधिक शिक्षक–कर्मचारी प्रभावित होंगे। पूर्व में तैनात शिक्षककर्मचारियों का एलआईसी से ग्रुप इंश्योरेंस कराया गया था। इसमें 84 रुपये से लेकर 175 रुपये तक अलग–अलग पे–स्केल के अनुसार इंश्योरेंस का पैसा शिक्षक–कर्मचारियों के वेतन से कटता था। कुछ साल पहले एलआईसी की ओर से इस योजना को बंद कर दिया गया। ऐसे में पहले से योजना में पंजीकृत कर्मचारियों को तो इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन 31 मार्च 2014 के बाद तैनात शिक्षक–कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।एलआईसी की ओर से इस योजना को बंद किए जाने के बाद भी कुछ समय तक 2015–16 में बीमा के लिए कटौती की गई, फिर बंद कर दी गई। शिक्षक–कर्मचारियों को यह राशि भी अभी तक वापस नहीं मिल पाई है। माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त सहायता प्राप्त शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षक–कर्मचारी अनिवार्य बीमा योजना से आच्छादित नहीं माने जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री ओम प्रकाश त्रिपाठी ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि यह कर्मचारियों को पेंशन, सामूहिक बीमा से वंचित रखने का षड़यंत्र है। तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राजमणि सिंह ने कहा है कि शासन ने सालों से काम कर रहे 2000 से अधिक शिक्षकों को सेवा से बाहर कर दिया था। अभी तक उनका पुराना बकाया वेतन भी नहीं जारी किया गया है। ऐसे में अब यह निर्णय उनके साथ अन्यायपूर्ण है। हर शिक्षक–कर्मचारी के लिए बीमा और पेंशन अनिवार्य होनी चाहिए। इसके लिए आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि ऐसे शिक्षक जो तदर्थ,अल्पकालिक खाली पदों पर नियुक्त हुए। बाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम के तहत नियमित हुए हैं। उनकी सेवा मौलिक नियुक्ति की तिथि 22 मार्च 2016 से ही अर्हकारी सेवा के रूप में गिनी जाएगी।

महिलाओं की नई संवेदनाएँ, परंपरा एवं आधुनिकता एवं इतिहास लेखन पर एक सप्ताह के ज्ञान पाठ्यक्रम का समापन

अलीगढ। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (जीआईएएन), अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) द्वारा 'महिलाओं की नई संवेदनशीलताः उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की उत्तर पश्चिमी परंपरा, आधुनिकता पर एक सप्ताह का ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आधुनिक और समकालीन दक्षिण एशिया की इतिहासकार और पाठ्यक्रम के विदेशी संकाय सदस्य प्रोफेसर सारा फ्रांसिस डेबोरा अंसारी (रॉयल होलोवे, लंदन विश्वविद्यालय, यूके) ने सात व्याख्यान दिए, जबकि अध्यक्ष और समन्वयक, सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडी, इतिहास विभाग, एएमयू प्रोफेसर गुलफशां खान ने पांच सत्रों में व्याख्यान किये। यह पाठ्यक्रम उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के पूर्व और विभाजन के बाद के इतिहास की समझ विकसित करने के लिए चयनित स्रोतों के विश्लेषण और मौजूदा इतिहासलेखन की आलोचनात्मक समीक्षा के माध्यम से प्रतिभागियों को महिलाओं और लिंग इतिहास से परिचित कराने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रोफेसर सारा अंसारी ने अपने पहले व्याख्यान में विशेष रूप से औपनिवेशिक दक्षिण एशिया के संदर्भ में, लिंग के साथ दोनों के संबंध को स्पष्ट किया। प्रोफेसर अंसारी ने कहा कि ब्रिटिश और भारतीय दोनों समकालीनों ने महसूस किया कि महिलाओं को इस अर्थ में बचाये जाने की जरूतर हो न केवल उनकी अपनी भलाई के लिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए। प्रोफेसर अंसारी ने दूसरे व्याख्यान में विशेष रूप से महिला शिक्षा के सवाल पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि तीसरे व्याख्यान में उन्होंने राष्ट्रवाद और महिलाओं के बीच संबंधों पर चर्चा की। चौथा व्याख्यान दक्षिण एशिया के विकास पर केंद्रित था जिसने भारत और भारतीय महिलाओं को दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ा। प्रो. अंसारी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के मताधिकार संबंधी बहसों में उनकी भागीदारी के बारे में बात की। पांचवें व्याख्यान में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में स्थापित महिला संगठनों की विशेष चर्चा की, जो वास्तव में पिछली शताब्दी में सुधारवादी व्यक्तियों और संस्थाओं के शुरुआती प्रयासों का परिणाम थे। छठे व्याख्यान में भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी की जटिल कहानी पर प्रकाश डाला गया। प्रोफेसर अंसारी का सातवां व्याख्यान नागरिकता से संबंधित मुद्दों और उससे उत्पन्न अधिकारों और जिम्मेदारियों पर केंद्रित था। पांच सत्रों में से पहले सत्र में प्रोफेसर गुलफशां खान ने कहा कि उत्तर भारतीय कुलीन मुस्लिम, उर्दू भाषी बुद्धिजीवियों, सैयद अहमद खान, उनके समकालीन नजीर अहमद (1833–1912) और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, (1837–1914), 1857 के आसपास या उसके बाद पैदा होने वाले सुविधाओं पर प्रकाश डाला

गंगा घाट पर बिना अनुमति के नहीं कर पाएंगे कार्यक्रम

नगर निगम ने जारी किया नया आदेश, निगम प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

वाराणसी। वाराणसी के गंगा घाट पर अब कोई कार्यक्रम किया, तो नगर निगम को शुल्क देना होगा। इसके लिए निगम प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। इसको लेकर नगर निगम बाइलाज बनाकर शासन से मंजूरी लेगा। इसको लेकर नगर निगम कार्यकारिणी की मीटिंग में निर्णय लिया गया। मेयर अशोक कुमार तिवारी ने निगम कार्यकारिणी की बैठक में सीमा विस्तारित क्षेत्रों में सरकारी जमीनों, तालाबों, कुण्डों के चिह्नांकन के बारे में जानकारी ली। गंगा घाटों पर आए दिन विभिन्न संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे नगर निगम को किसी प्रकार की आय नहीं होती है। घाटों की सफाई व रख रखाव की जिम्मेदारी नगर निगम की है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने अब घाटों पर होने वाले आयोजनों पर शुल्क लेने का निर्णय लिया है। बिना बाइलाज नगर निगम किसी प्रकार के शुल्क की वसूली नहीं कर सकता। इसलिए शुल्क लेने के लिए निगम प्रशासन को बाइलाज बनाना होगा। इसका गजट होगा। इस पर आपत्तियां ली जाएंगी। इन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद इसकी मंजूरी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

141 संसद सदस्यों का निलंबन सीधे लोकतंत्र की हत्या है : रालोद

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव विजय कुमार लाल श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रोल है परंतु कि संसद के सामने माथा टेकना वाले पीएम मोदी के राज में 141 सम्मानित संसद सदस्यों को संसद से निष्कासित किया गया जो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। यह सीधे लोकतंत्र की हत्या है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि मोदी की बीजेपी गाँधीजी,लोकनायक जय प्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, अम्बेडकर ,डॉक्टर लोहिया के विचारों से दूर हो गई है।बीजेपी मूल्यहीन पार्टी है जो तानाशाही राज करना चाह रही है। देश की जनता ने आजादी के बाद तानाशाही राज नहीं बर्दाश्त किया है।1977 में तानाशाही के खिलाफ जनता पार्टी की सरकार बनी थी वैसे मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन यूपी में डबल इंजन की सरकार का बैंड बजा देंगी। लोकसभा की 80 में 8व सीट जीतेगी। मोदी राज में महंगाई, बेरोजगारी और उन्माद बढ़ा, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई स गांव का विकास नहीं हुआ। कुपोषण और गरीबी से देश जूझ रहा है। यदि गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल किसानों के महान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती तक यूपी सरकार ने नहीं घोषित किया तो लखनऊ में 26 दिसंबर को धरना ,प्रदर्शन होगा।

पर्यटन मंत्री आज से आगरा, मैनपुरी एवं फिरोजाबाद दौरे पर

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह 21 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक आगरा, फिरोजाबाद तथा मैनपुरी के भ्रमण पर रहेंगे। पर्यटन मंत्री कल अपराह्न 01 बजे से प्रस्थान कर अपराह्न 04 बजे तक बटेश्वर धाम आगरा पहुंचेगे। सीएम के कार्यक्रमों के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अगले दिन 22 दिसम्बर को पूर्वाह्न 09 बजे से अपराह्न 01 बजे तक मैनपुरी में जनसमस्याओं की सुनवाई करेंगे। इसके उपरान्त सरस्वती विद्या मंदिर बंशीगौहरा मैनपुरी में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयन्ती पर आयोजित गणित विज्ञान प्रदर्शनी एवं मेले में शामिल होंगे। इसके पश्चात नगला निरंजन मैनपुरी में सीडीओ आफिस तक सीसी रोड, सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। 24 दिसम्बर रविवार को सिरसागंज फिरोजाबाद कैम्प कार्यालय में जनसमस्याओं की सुनवाई करेंगे। 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयन्ती पर शिलान्यास एवं लोकार्पण आदि कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपराह्न 03 बजे क्रिश्चियन मैदान मैनपुरी में 72वें यूपी स्टेट सीनियर पुलिस,महिला वॉलीवॉल चौम्पियन कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होंगे और अगले दिन 26 दिसम्बर को दोपहर तक लखनऊ वापस आयेंगे।

'आयुर्वेद से किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम का सफल इलाज हिम्स में है संभव : आचार्य मनीष

लखनऊ। किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम का सफल इलाज आयुर्वेद से पूरी तरह संभव है। यह बातें हिम्स के डॉक्टर ने 20 दिसंबर 2023 को हिम्स लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहीं। हिम्स आयुर्वेद के संस्थापक आचार्य मनीष आयुर्वेद के प्रचार–प्रसार के लिए निरंतर सक्रिय हैं और लोगों को अपनी पुरानी विरासत से जागरूक कर निरोग काया का मंत्र दे रहे है। हिम्स लखनऊ में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हिम्स में शरीर की अंदरूनी शक्ति बढ़ाकर किडनी, कैंसर, लिवर, शुगर, बीपी और दिल के रोगों को रिवर्स करने पर जोर दिया जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अभिषेक शिवहरे भी शामिल थे। संबोधन के अवसर पर डॉक्टर अभिषेक ने कहा, षविभिन्न अस्पतालों में बहुत समय और पैसा खर्च करने के बाद विभिन्न डायलिसिस रोगी हमारे अस्पताल में आते हैं। हिम्स में हमारी टीम उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करती है और हमने अपने कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को कुछ महीनों के भीतर ही पूरी तरह से ठीक किया है। योग और मेडिटेशन गुरु और हिम्स के संस्थापक आचार्य मनीष ने कहा, षहिम्स में, हमारा लक्ष्य किसी भी बीमारी के मूल कारण का पता लगाना है। इसके लिए हम विशेष तौर पर इंटीग्रेटेड विज्ञान का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी का इलाज कर सकते है। न जाने कितने ही किडनी, लीवर, हार्ट और कैंसर के मरीजों के लिए हमारा आयुर्वेदिक इलाज उनके जीवन में आशा की किरण बनकर आया है। हमारे पास कई ऐसे मरीज भी आये है जो कि ठीक होने की उम्मीद पूरी तरह से खो चुके थे परन्तु आज बिल्कुल स्वस्थ है। हिम्स में आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी आदि जैसे विज्ञानों का उपयोग करके रोगों का इलाज किया जाता है। यहां बाजरा और जड़ी–बूटियों से बना भोजन रोगियों को उनके सही इलाज और स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रदान किया जाता है। हिम्स पोस्ट्यूरल थेरेपी का उपयोग भी करता है जो डायलिसिस को 70ः तक रोक सकता है। इससे 100ः हाई बीपी के रोगी बिना किसी दवा के तुरंत अपना बीपी नियंत्रित कर सकते हैं। यह गौर करने वाली बात है की हिम्स में मरीज ैठप कैशलेस AAROGYA संजीवनी पालिसी के माध्यम से मुफ्त इलाज भी पा सकते है। आज देश भर में सौ से अधिक शुद्धि क्लीनिक मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हिम्स में डॉ. अमर सिंह आजाद, डॉ. खादर वल्ली, डॉ. पांडे और डॉ. बीआरसी जैसे विशेषज्ञों की देखरेख और नेतृत्व में पुरानी से पुरानी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।

प्रति छात्र व्यय घोषित करने के आदेश का अनुपालन न करने पर

माननीय उच्च न्यायालय ने जारी किया अवमानना नोटिस

लखनऊ। माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 3118/2023 (सी/एम लखनऊ एस्थेटिक डेवलेपमेन्ट सोसाइटी बनाम श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव शिक्षा, लखनऊ व अन्य) में सुनवाई करते हुए वाद संख्या 15790/2019 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2022 का अनुपालन न करने के लिए दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, शिक्षा, लखनऊ को अवमानना का नोटिस जारी किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया कि स्टैंडिंग काउन्सल को अनुपालन का हलफनामा जमा करने के लिए समय देने के बावजूद आज तक आदेश दिनांक 26.08.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त अवमानना आवेदन में आदेश दिनांक 15.12.2023 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय ने अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसे न कर पाने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय इसके लिए दोषी प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दे सकती है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुरूप प्रतिपूर्ती राशि का निर्धारण करना होता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्ष 2013 से अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। इस संबंध में लखनऊ लखनऊ एस्थेटिक डेवलेपमेन्ट सोसाइटी ने वर्ष 2019 में माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या 15790 दाखिल किया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.08.2022 के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में प्रति छात्र व्यय की घोषणा करने के लिए निर्देश दिया था।

युवक ने कमरे के पंखे से लटककर लगाई फांसी,पुलिस जांच में जुटी

वाराणसी। वाराणसी में बुधवार को चोलापुर क्षेत्र के जगदीशपुर में मंगलवार की रात एक युवक ने कमरे के पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह युवक देर तक नहीं उठा तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, धक्का मारा तो गेट खुल गया। अंदर शव पंखे से लटकता देखकर कोहराम मच गया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी आ गए। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने शव उतरवाया और परिजनों से जानकारी ली। पिता की तहरीर पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जगदीशपु निवासी रोशन अली उर्फ सनी पुत्र अलिवास खान (24) रात में मंगलवार शाम दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था। रात में घर आया और खाना खाने के बाद कमरे में सोने चला गया। सुबह कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिवार के लोगों ने पहले दरवाजा खोलने का प्रयास किया। जब दरवाजा नहीं खुला तो खिड़की से देखा तो वह पंखे से लटक रहा था। यह देख घरवालों के होश उड़ गए। परिवार में चीख– पुकार मच गई। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान किसी ने घटना की जानकारी चोलापुर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घरवालों से पूछताछ के साथ ही शव को कब्जे में ले लिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी जानकारी एकत्रित की।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com

R.N.I.- UPHIN/2012/45127

नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।